3229
18/4/12

पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

असंशोधित

28 MAR 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्र०सं०...633...तिथि...18/4/12

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । विधायी कार्य लिये जायेंगे । बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक का व्यवस्थापन होगा । आज इसके लिये एक ही दिन का समय निर्धारित है । वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिये कुल २ घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा ।

जनता दल यूनाइटेड	- ५७ मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- ४५ मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	- ११ मिनट
कांग्रेस पार्टी	- २ मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- १ मिनट
सी०पी०आई०	- १ मिनट
निर्दलीय	- ३ मिनट
कुल :	१२० मिनट

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

"बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २०१२"

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

"बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २०१२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २०१२ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ । अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूं ।

माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २०१२ पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २०१२ पर विचार हो ।"

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खण्डशः लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"खण्ड-२ एवं ३ इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-२ एवं ३ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"खण्ड-१ इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-१ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि -

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूं ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

"बिहार विनियोग (संख्या-२) विधेयक, २०१२ स्वीकृत हो।"

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बजट पेश किया है, कुल व्यय बजट प्लान एवं नन-प्लान ७८,६०० कुछ करोड़ रू० का जिसमें २८ हजार करोड़ प्लान एक्सपेंडिचर में खर्च होना है । इस पूरे बजट में सरकार ने अपने स्त्रोत से १८ हजार करोड़ रू० का उपबंध किया है और ६० हजार करोड़ रू० अन्य मदों से - भारत सरकार हो, ऋण हो, कई मदों से लेनी है । इस परिस्थिति में विभिन्न विभागों में जो उपबंध किये जायेंगे उसके लिये सरकार इस सदन से, हमलोगों से ऑथरिटी चाहती है । ऑथरिटी तो हम देंगे ही, मगर किस बात की ऑथरिटी चाहते हैं ? पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, १६.३ तक हमने कुल प्लान बजट का लगभग ५१ प्रतिशत खर्च किया है और १४ दिन में सरकार क्या यह सुनियोजित ढ़ंग से खर्च कर पायेगी ? इसका मतलब है कि यह जो

काम ११ महीने में नहीं हुये, १४ दिन में लूट का पर्याय बनेगा, दूसरा कोई सवाल पैदा नहीं होता है । आज इस सदन में सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने इस मार्च लूट की सत्यता को बड़ी बखूबी इस सदन में रखा है, हम उम्मीद करते हैं सरकार को इसपर गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये कि यह मार्च लूट कैसे बन्द होगा ।

यहाँ कृषि रोड मैप की व्यापक चर्चाएँ, दो दिन का कृषि रोड मैप पर चर्चा, पहली बार इस सदन में गाँव और किसान के लिये दो दिन की चर्चा, यह काबिले-तारीफ है । इससे हम फर्क नहीं कर सकते हैं । पहली बार गाँव एक सवाल बनकर खड़ा हुआ इस राज्य में, यह हमलोगों के लिये गौरव का विषय है । मगर जब पूरे बजट के प्रावधानों को देखा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कृषि क्षेत्र में जो हमारा योगदान है, आज भी १८.४ प्रतिशत का जी०एस०डी०पी० में कृषि क्षेत्र का योगदान है और उसके लिये मात्र ४.२९ प्रतिशत का खर्चा यह गाँव के इतने बड़े सेक्टर जहाँ ८८.७ प्रतिशत लोग जीते हैं, इतने बड़े सेक्टर के लिये बेईमानी नहीं तो क्या है ? मैं तो यह समझता हूं कि कम से कम आप कृषि क्षेत्र से, गाँव के लोगों से जितनी आय लेते हैं, कम से कम उतना उपबंध कर दिया जाता, उसके विकास के लिये कम से कम उतना प्रतिशत राशि खर्च कर दी जाती तो यह भी उपकार नहीं होता, मगर यह ४.१ प्रतिशत का उपबंध यह तो बेईमानी के सिवाय इस बड़े सेक्टर के लिये कुछ नहीं है । अध्यक्ष महोदय, पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में जो अभी प्राप्त हुआ है, उसमें एक रेकर्ड है, मैं सदन के सामने इसको पढ़ देना चाहता हूं कि कैसे कृषि विकास में उतार-चढ़ाव का ट्रेन्ड है, भयंकर है । वर्ष २००७ में ३०.२ प्रतिशत के कंपेरिजन में २००७-०८ में -७.३ प्रतिशत, २००८-०९ में १२.३ प्रतिशत।

...क्रमशः...

श्री चन्द्रशेखर : (क्रमशः) २००९-१० में पुनः कम्प्रेटिभली ९.१ प्रतिशत और आज फिर ७.७ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखायी गयी है, यह खतरनाक ट्रैंड है । सरकार इसको स्थिर करने के लिए अगर कोई विशेष उपाय नहीं करेगी तो ग्रामीण जीवन बेहाल है, आगे भी बेहाल रहेगी, सिर्फ कृषि रोड मैप के चर्चा से बहुत ज्यादा कल्याण होने वाला और कुछ होने वाला नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में एक अखबार है, यह गत वर्ष का है । इसमें जो आपने बजट पेश किया था, इसमें लिखा हुआ है आपके ही सरकार के द्वारा जो रिर्पोटिंग हुई है कि २६ प्रतिशत से ०९-१० में कृषि क्षेत्र का योगदान जी०एस०डी०पी० में २६ प्रतिशत था और यह २०१०-११ में १९ प्रतिशत हो गया । यह बात और आज मैं आपको बताऊं जहां १९.९ प्रतिशत पिछले दफा कृषि क्षेत्र से आमदनी दिखायी गयी थी, उसमें आज १ प्रतिशत की घटोत्तरी है । तो फिर आपने जो कृषि रोड मैप लाया, इससे क्या फायदा हुआ, उससे १ प्रतिशत हम ही घट गये तो क्या फायदा हुआ ? यह स्पष्ट परिलक्षित होता है अध्यक्ष महोदय । मेरा कहना है कि आप ऑथोरिटी लें मगर एक ईमानदार सोच और प्रयास होना चाहिए अध्यक्ष महोदय । अगर हम इतने बड़े सेक्टर जहां ८८.७ प्रतिशत जनसंख्या रहती है, उसकी अगर हम आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं तो उद्योगों में काम करने वाले लोगों, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों, मतलब प्राईमरी सेक्टर को छोड़कर के सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ाकर के राज्य की विकास की कल्पना बेईमानी के सिवा कुछ नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। हम यह इसलिए इसको मूल रूप से चर्चा में लाये कि कृषि रोड मैप का जबर्दस्त नारा देखा, हमें भी खुशी हुई, हमने पहले भी कहा कि दो दिन का बहस कराईए, यह भी अच्छी बात है लेकिन बहस के पीछे कहीं सरकार की मानसिकता इतने बड़े सेक्टर के लोगों की बेहतरी की नहीं है, एक्सप्लायटेशन का है अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या प्रतिशत है ? हम आंकड़े देते हैं कि पुरूष साक्षरता ७३ प्रतिशत बढ़ा, महिला साक्षरता ५३ प्रतिशत बढ़ा और इसी संबंध में एक इर्म्पोटेंट जनरल है, यह इकोनोमी एंड पोलोटिकल वीकली, इस ने बड़े ही खतरनाक सर्वेक्षण करके बिहार और देश के सामने रखा है कि प्राईमरी स्कूल में एक-एक शिक्षक एक साथ तीन से चार क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाकर के वर्ग अध्ययन करा रहे हैं । कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आशा हम कर सकते हैं । एक क्लास में जहां एक शिक्षक ३-४ वर्ग के लोग को बैठाकर के शिक्षा ग्रहण करावे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है ? हाईस्कूलों में और प्राईमरी स्कूलों में चपरासी का वेतन नियोजित शिक्षकों से ज्यादा है, कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हमलोग मूल्यांकन करने के लिए बैठे हुए हैं, कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आशा कर रह हैं ? इस राज्य में अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में भयंकर शिक्षकों की कमी है । जहां आर०आर०एस० कॉलेज, मोकामा में ४४ में १४ शिक्षक काम कर रहे हैं, जहां एम०डी०कॉलेज, नौबतपुर में ३२ में ५ शिक्षक काम कर रहे हैं बॉटनी, जियोलॉजी, केमीस्ट्री, हिस्ट्री कई डिपार्टमेंट में एक भी शिक्षक नहीं है, फिर भी यह कहने से १५ साल क्या हुआ, आपको भी अध्यक्ष

महोदय सरकार को भी ७ साल होने जा रहा है । सिर्फ १५ साल कहने से राज्य का विकास संभव नहीं है । जहां नवअंगीभूत महाविद्यालयों के ३६ महाविद्यालयों के शिक्षक ज्यादा हैं, कॉलेज में ३० वर्ष से पढ़ा रहे थे, साढ़े तीन साल से सरकार उसका वेतन बन्द कर दी है और अभी तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया है । एक तरफ शिक्षक की कमी है महाविद्यालयों में, दूसरी तरफ शिक्षक को निकालने में सरकार मशगूल है । पता नहीं कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना हमलोग इस सरकार से कर सकते हैं, कौन सी आशा कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय । स्वास्थ्य का सवाल है, हम पटना में जब भी सदन चलता है और मीटिंग के दरम्यान आते, पेसेंट को लेकर के पी०एम०सी०एच० में जाते, लगातार साल भर में कम से कम १०० बार जरूर गये होंगे और क्या हृदय विदारक स्थिति है अध्यक्ष महोदय । अगर कोई माननीय सदस्य अगर हृदय पर हाथ धर करके कह दे कि स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, कुछ मिलने वाला नहीं है । ६-६ घंटा, ४-४ घंटा फोन करके प्रेशर डालकर के आज एक सरकार को वहां से एक इनफॉरमेशन लेना चाहिए कि कितने पेसेंट एडमीट होते हैं गंभीर रोगों के, चाहे वह न्यूरो का केस हो, चाहे इन्टेसटाईनल सर्जरी का केस हो, चाहे हर्ट सर्जरी का केस हो और कितना प्रतिशत उसमें सर्जरी होता है इन्ट्री और सर्जरी का आऊटपुट क्या है, अगर देख लेंगे अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कोई ऑफिसियेटिंग इनफॉरमेशन नहीं दिया हूँ लेकिन जा-जा कर देखता रहा हूँ कि बिना पैरवीकार भी ३ प्रतिशत भी सर्जरी नहीं होती है । कहां राज्य को ले जा रहे हैं स्वास्थ्य के मामले में अध्यक्ष महोदय तो और अस्पतालों की क्या स्थिति हो सकती है ? एक अखबार का कतरन है मेरे हाथ में, एक भी नहीं मिले डाक्टर कर्मी विधायक अस्पताल, पटना में । ८ बजे से ओ०पी०डी० चलती है, ९.३० बजे स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त वहां छापा मारते हैं और एक भी डाक्टर-कर्मी नहीं मिलते हैं । मैं स्वयं पता नहीं और माननीय विधायक जाते होंगे या नहीं । मैं स्वयं अस्पताल में ३ बार गया और एक बार भी सीटिंग प्लेश में डाक्टर नहीं मिले । आधा घंटा बैठाया गया, चाय वगैरह पिलाया गया तब माननीय डाक्टर साहेब आते हैं, लगता है कि कहीं भगवान के घर से उतर रहे हैं, ड्यूटी उनका अस्पताल में बैठने का नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जहां विधायक अस्पताल में डाक्टर की इस तरह से उपस्थिति हो सकती है तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र में और जिला मधेपुरा से लेकर के कोशी के स्वास्थ्य केन्द्रों में अस्पतालों में क्या स्थिति हो सकती है, यह कहने की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय । यह तमाम बातें जहां स्वास्थ्य का यह हाल है, जहां रोड का यह हाल है । रोड की आज क्या स्थिति है, ३८,०००कि०मी० सड़के प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना से लेकर के भारत सरकार एवं विश्व बैंक सम्पोषित सड़के ३८,०००कि०मी० सड़के जो हमारे आदरणीय नेता यू०पी०ए० गवर्नमेंट में जो मजबूत जिम्मेवारी निभाते थे, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव और फिर आदरणीय मंत्री श्री रघुवंश बाबू के कृपा से बिहार को ३८,०००कि०मी० सड़के मिली १६,०००करोड़ रू० का, आपके सर्वेक्षण में इसका कहीं जिक्र नहीं है । मैं क्या समझूं यह बेईमानी नहीं तो यह सरकार क्या कर रही है बैठ

करके, कम से कम पूरा सर्वक्षण रिपोर्ट में कहीं तो चर्चा हो जाता । यू०पी०ए०-१ के गवर्नमेंट में जहां ५-५ मंत्री थे तो इस सरकार को, इस बिहार को विकास के लिए ३८,०००कि०मी० सड़क मिल गया मगर २९ महीनों में ३८ सेंटीमीटर सड़क भी कहीं प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क का क्यों नहीं मिला ? यह सरकार की विफलता को नहीं दर्शाती है, क्या कारण है इसके, क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, कहीं सरकार में दोष है या नहीं, यह खोज का विषय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार अपने योगदान को देने में या हो सकता है इन राशियों को कहीं दूसरे जगह बन्दरवाट करके इनफॉरमेशन यूटिलीटी देने में तो कमी नहीं कर रही है । मगर जो भी बात हो, मेरे कहने का मतलब है अगर ३८,०००कि०मी० बिहार के विकास में सड़क यू०पी०ए०-१ के गवर्नमेंट में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों के ताकत से आयी भारत सरकार को प्रेशर बनाकर के तो इसकी चर्चा भी नहीं होना, यह बेईमानी के सिवा कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

(इस अवसर पर सभापति(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,स०वि०स०) ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, हम रात-दिन बिजली के सेक्टर में कौन सी ऑथोरिटी चाहती है यह सरकार, बिजली के सेक्टर में हम कोशी इलाके के चाहे भेलवा हो, बरियारी हो, गड़िया हो, कई गांव ऐसा है, दर्जनों-दर्जन गांव जहां तार चला गया, पोल चला गया, १० वर्षों से ट्रांसफर्मर नहीं लग रहा है लेकिन १०-१० बिल चला गया । उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, यह स्थिति है । कहीं तार और पोल भी नहीं लगा, कहीं लगा तो टूट गया मगर बिल जा रहा है । इसीलिए अगर सरकार ऑथोरिटी और उपबंध मांगती है तो हमको लगता है, देना तो है ही, यह एक लाचारी है लेकिन सरकार को इसपर विचार करना चाहिए । ....क्रमशः.......

...क्रमशः...

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मैंने जो कहा, तमाम बातें, जहांतक गृह विभाग का मामला है, कल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिस बात को रखा कि सरकार के, रूलिंग पार्टी के एक विधायक जावेद अख्तर के किडनेपिंग में २ करोड़ की फिरौती मांग करके ५५ लाख रूपया लेने पर मजबूर कर दिया, यह उसकी पत्नी ने लिखकर दिया है । जहां जमुई की घटना पूरे राज्य को शर्मसार करनेवाली है, पूरे परिवार को किडनेपिंग करके...

सभापति (श्रीअमरेन्द्र प्रताप सिंह) : अब आप समाप्त करें, अब आप अपने भाषण को कनकलुड करें।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, हमलोग नये सदस्य हैं, मोटा-मोटी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्थिति है, उसपर सरकार ईमानदार प्रयास करे । भ्रष्टाचार, सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक श्री अवनीश कुमार सिंह जी की चिटठी मेरे ही पास नहीं है, बल्कि तमाम सदस्यों के पास है, अगर उस चिटठी को पढ़ लिया जाय, अगर सरकार संवेदनशील है तो पढ़ ले, माननीय विधायकों की जो स्थिति है, हम तो उम्मीद करते हैं कि एक आदमी सत्ता में बैठकर कई प्रखंड में, जितना प्रखंड हो बिहार में, हर प्रखंड में एक-एक मुख्यमंत्री बना दे । विधायी संस्था को कमजोर करके विधायकों को नीचा दिखाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश तो इस जन्म में नहीं, सात जन्म में भी नहीं मिट सकता हे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्री रामेश्वर पासवान : सभापति महोदय, अभी सरकार के द्वारा जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत सदन में है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूँ । सभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य एक प्रोफेसर भी हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बात बोलेंगे जिससे खास करके राज्य के हित में होगा और विनियोग विधेयक से संबंधित जो बातें होंगी, उसपर ज्यादे सर्वाड़िग प्रकाश डालेंगे । लेकिन उन्होंने केवल एक ही रूख अपनाया है कि दिन को रात और रात को दिन कहना । देखकर भी यह नहीं कह पाते हैं कि यह दिन है । इसलिए माननीय सदस्य को अभी कहते हैं कि चश्मा नहीं बदलिए तो कम-से-कम नजरिया तो बदलिए । अगर नजरिया आपकी बदल जायेगी तो मैं समझता हूँ कि सब काम आपको सही-सही नजर आने लगेगा । मैं इससे शुरू करूँ कि-

"मंजिलें उन्हीं को मिलती है, जिनके सपने में जान होती है,
और उड़ान पंखों से नहीं, होसले से होती है" ।

इसलिए आपने पंखों की बात पर किया.....व्यवधान... सभापति महोदय, पहले इनका सपना ही बेकार है । पहले सपना तो संजोइए, उसमें जान नहीं है तो बेजान की बात मत कहिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : रमण जी, आप कवि आदमी हैं, अगर है तो इस कविता का जबाब दीजिए कविता में ।

श्री राम लषण राम रमण : "वह उड़ान क्या भरे, जिसमें जान ही न हो" ।

श्री रामेश्वर पासवान : सभापति महोदय, मैं कवि नहीं हूँ कि जो इस प्रकार की बात करूँ, वह तो तुक्कर भी हैं, कहते हैं कि किल्लत है किल्लत है, जहां सब कहते हैं कि वहां कोई किल्लत नहीं है, हर जगह मिल्लत है । जब ऐसी बात हो तो तब फिर ऐसी बात कहां से आती है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बड़े विद्वान, जानकार एवं सुलझे हुए व्यक्ति हैं । इस तरह की बात को लेकर कुछ बात जो कहना चाहते हैं, वह थोड़ा सोचते हैं कि जरा रास्ते से डायभर्ट कर जाय लेकिन एक बात है कि पासवान, पासवान है, जहां आसमान तक को छूने का हौसला रखता है, उसको फिर कोई छूने की बात नहीं है । हमेशा पासवान, पासवान है, सब जगह उंचा रहेगा । रक्षक है, रक्षक और सब उसके बाद ही रहेंगे, पासवान उपर ही रहेगा ।

(व्यवधान)

सभापति (श्रीअमरेन्द्र प्रताप सिंह) : शांति-शांति ।

श्री रामेश्वर पासवान : सभापति महोदय, अभी-अभी हमलोग बजट की बात कर रहे थे और बजट आप देख रहे हैं कि किस तरह का बजट, जब देख रहे हैं कि बजट पहले क्या था? वर्ष २००४-०५ में क्या था और आज का बजट क्या है ? बजट की बढ़ोत्तरी ही यह परिचायक है कि हम कहां जा रहे हैं । हमारे विकास की गति बढ़ रही है या घट रही है तो पहले आप बजट को देखिए कि वर्ष २००२, २००४ और २००५ का बजट और आज का बजट क्या है । वर्ष २००४-०५ में क्या था, आप जानते होंगे लेकिन आज का बजट ठीक २८ हजार, यानी करीब लगभग ८० हजार करोड़ की बजट है २०१२-१३ की । जिसकी हम स्वीकृति देंगे तब विकास की गति आगे बढ़ेगी अथवा आपका, हमलोगों का वेतन भी नहीं मिलेगा, टी०ए० भत्ता भी नहीं मिलेगा, घर जाना मुश्किल हो जायेगा, इसलिए स्वीकृति आप दें और उसपर कहिए कि विकास की गति बढ़े और इसकी स्वीकृति पहले बिना किसी प्रकार के डिसकसन का दे दीजिए, लेकिन एक परम्परा है, उसको निर्वहन करना है, यह ठीक है । पहले आप देखते थे, पहले हमलोग बजट के संबंध में बात किया करते थे, एक-एक बात शुरू से लेकर कृषि की बात हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कृषि रोड मैप की बात शुरू किया । मुझे लगता है कि बिहार में जिस समय हमारे पूर्व मंत्री, नेता नाम नहीं लेना चाहिए, नेता हमारे लालू जी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे लेकिन बंटने के बाद बिहार में क्या रह गया, एक कृषि और पर्यटन की सिवाय क्या रह गया ? आज उसी कृषि को अगर कोई उसके बारे में विशेषज्ञ हुए और तकनीकी के रूप में एक चित्र खींचकर के, मैप देकर

उन्नति के रास्ते पर यही रास्ता हमारे लिए सुखद हो सकता है, उन्होंने एक रोड मैप दिया और रोड मैप २००५-०६ में और २००७ से लेकर २००८ तक की बात, मैं २०१०-११ की बात करता हूँ, जिसमें आपका ७३४ करोड़ था आपका कृषि बजट और २०११-१२ में ७९७.८६ था और २०१२-१३ में १२०० करोड़ का हो गया । यह क्या बताता है, क्या परिलक्षित करता है ? यह बताता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और कृषि रोड मैप की तरह जो हम देखना चाहते हैं, कैसे हम कृषि को विकसित करें ताकि हमारे बिहार के वासी सुखी हों ही, साथ-ही-साथ पूरे देश और विदेश में भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारे बिहार का कोई भी ब्यंजन, कोई भी अनाज या ब्यंजन देश के हर थाली में जाय, विश्व के हर थाली में जाय । आज यहां नहीं पूरे राष्ट्र में यह फौलो कर रहा है । पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही हे । हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेश गये, लंदन गये, वहां भी इसकी चर्चा हुई । एक बिहार रोड मॉडल की वहां भी चर्चा हुई, देश की बात नहीं, विदेश में इसकी चर्चा हो रही है । जहां हम जापान और इंगलेंड की बात करते हैं, वहां भी इसकी चर्चा हुई कि बिहार अग्रसर की ओर बढ़ रहा है, उन्नति की मार्ग पर बढ़ रहा है, जो कहीं किसी के तुलना के रूप में नहीं आते हैं । आज हमको फर्क है, गौरव है कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी जैसे नेता हमारे बिहार को मिला, हमलोगों को मिला जो आगे की ओर, विकास की ओर पूरे बिहार को ले जा रहे हैं । इसके लिए सभी को फक्र है । यह एक गौरव की बात है और लोग महसूस कर रहे हैं और आज लोग शान के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं और जो नहीं बिहारी हैं, वह कहते हैं कि काश हम भी बिहारी होते, वे आज ऐसा महसूस करते हैं । कृषि रोड मैप के द्वारा आज १२०० करोड़ की योजना हमारे कृषि विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है ।

(क्रमशः)

श्री रामेश्वर पासवान : क्रमशः.........जिससे हर किसान को खाद, बीज चाहे मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना हो, चाहे कल्टीवेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए जिस प्रकार के यंत्र हो वो सभी मुहैय्या सबसिडी के रास्ते से दे रहे हैं, सबसिडी देकर उनको देना चाह रहे हैं और उसके लिए सबसिडी खासकर के छोटे-छोटे किसान जैसे पावर टीलर वगैरह है उसमें ६० परसेंट है। आपके ट्रैक्टर पर ६० परसेंट है, वैसी हालत में जो परचेज नहीं भी करना चाहते हैं वो भी कृषि को ले रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है। साथ ही साथ उसमें जो हमारे कृषि रोड मैप में शामिल किये हैं तो सभी १४ विभाग का उसमें मिश्रण है, योग है जिसमें पहले इरीगेशन, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर तो है है, कृषि तो है ही साथ ही साथ इरीगेशन, इलेक्ट्रीफिकेशन और आपका कम्युनिकेशन, कॉपरेटिव, पशुपालन जितने भी विभाग हैं वो सभी इसमें कृषि को कितना सहयोग मिल सकता है उन सभी का उसमें समावेश किया गया है। इस तरह से १४ विभागों को उसमें सहयोग है और उनके सहयोग से ये कृषि का रोड मैप की सफलता हम प्राप्त करेंगे और हमको और आपको जो उससे परिणाम मिलेगा- ये हमारा कृषि प्रधान देश ही नहीं जो बिहार है सबसे सर्वोपरि और हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी का जो सपना है कि पूरे देश में सभी के थाली में एक बिहार का व्यंजन उपलब्ध हो यह सपना पूरा हो। आज २०१२-१३ में- २००० से पहले और अभी की तुलना में कृषि में ४० गुणा की वृद्धि हुई है, ये आपके बजट में ४० गुणा की वृद्धि हुई तो उस समय से आप कह सकते हैं कि अभी कहां थे और कहां हम आ गये और कहां हम जा रहे हैं उससे बिलकुल सोचकर के आगे बढ़ने में हमलोगों को मदद करनी चाहिए सरकार को ताकि हम आगे बढ़ाकर के कुछ करें। अब बात को ज्यादा नहीं कहकर के हम शिक्षा विभाग की बात कहेंगे। आश्चर्य होता है कि शिक्षा विभाग की जो दुर्दशा हो गयी थी, सभी लोग कहते हैं कि स्कूल क्या था, स्कूल के छत पर छप्पर नहीं था, फूस नहीं था और आज रास्ते में चलते हैं रोड में तो लगता है कि ठीक सरस्वती का मंदिर है, अगर सरस्वती हैं तो उस मंदिर में आपको नजर आयेगी, आप एक लेक्चरल हैं, प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं और उस विद्वता के दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन करें तो मैं समझता हूँ कि कहेंगे कि ठीक सरस्वती अब हैं, उस समय नहीं थी। जब शिक्षा ही हो गया तो उसमें बाकी क्या रहा। अब जो भी इस प्रकार की बात है हम किसी भी दृष्टिकोण से कैसे आपको हम शिक्षित कर सकते हैं। अरे आंगन से लेकर के आंचल योजना क्या है, आंगन से लेकर के आपके विश्वविद्यालय तक कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिक्षा के लौ से, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच से, हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री जी की सोच से कौन नहीं लाभान्वित हुआ है। आप वित्तरहित शिक्षा की बात देख लीजिए, क्या हालात थे और लोग कहते थे कि माफियाओं का सरगना सबकुछ कर लिया, लेकिन उनको माफिया लोग चंदा वगैरह करके कुछ लोगों को बहाल कर लिये लेकिन खा जाते थे और शिक्षा का नामोनिशान- स्कूल पर भी शिक्षा का खासकर के कुछ बात नहीं थी, छप्पर और फूस नहीं था उसपर, लेकिन आज देखते हैं मंदिर के साथ-साथ जितने भी लोग वित्तरहित स्कूल है उस वित्त रहित स्कूल में सभी दुहाई देते हैं, बड़ाई करते हैं कि कुछ न कुछ हमको राहत मिली और आज उतने पर नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है- ये ऐसा कुछ चिंतन करते रहते हैं कि सही मायने में जो शिक्षक है, सही मायने में जो शिक्षक हैं, सही मायने में जो पढाते हैं

वो उन लोगों को जो वाजिब मिलना चाहिए वह नहीं है। वह शिक्षा के माफिया लोग जो हैं वो खा जाते हैं। उन्होंने बिलकुल ये सोचा है कि ठीक उनको सही मायने में जो शिक्षक वहां पर शिक्षण का कार्य करते हैं उनको सही मायने में उनके पासबुक में उनको पैसे मिले, उनको सही पैसा मिलना चाहिए। ये वित्तरहित जो आपके स्कूल हैं या विद्यालय हैं और आपके उच्च विद्यालय हैं, कॉलेज हैं उन लोगों की बात इस प्रकार है और ये क्या दिखाता है शिक्षा- आप जब देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल से लेकर के आज प्लस टू तक का जो विद्यालय में खासकर के लड़के लड़कियां हैं उनको क्या नहीं मिला, साइकिल मिला, पोशाक योजना मिली और ये प्लस टू जो रोटी, सत्तू, भुंजा खाकर के वो आइ०ए० पास करेंगे और उसके बाद उनका प्रमोशन डिग्री कॉलेज में इस प्रकार की बगल में एक ही जगह इंटरमीडियेट भी, प्लस टू भी और उच्च विद्यालय भी वो खाकर रोटी, भुंजा, सत्तू खाकर के इतने साक्षर और शिक्षित हो जायेंगे कि ठीक पहले जो आंध्रा और कर्नाटका के बारे में लोग चिंतन करते थे कि वहां बड़े विद्वान लोग हैं और इस प्रकार की बात कि सभी लोग शिक्षित लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन आज फख्र के साथ हमलोगों को कहना पड़ता है कि हमारी लड़कियां, हमारी माता और बहनें वो भी तो हो ही रहे हैं, साथ ही हमारी बेटियां और बहनें- लड़कियां जब साइकिल पर और पोशाक पहनकर चलती हैं तो छाती फूल जाती है हमारी माता, बहनें, आपको और हमको भी, ये कहना पड़ता है कि आज हमारा बिहार अगर है तो कर्नाटका और आंध्रा से कम नहीं और कहते हैं कि पेरिस बना देंगे, अरे पेरिस तो इस प्रकार के बाद होता क्या है। अभी आप पटना में देखिये रोड की बात कर रहे थे, आप रोड में देखियेगा चलियेगा तो साल दो वर्ष पहले चले थे तो भूल जाइये, जितने पुल और रोड बने हैं.....व्यवधान....प्रतिपक्ष के नेता से हमको ये उम्मीद नहीं थी।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,ने०वि०द० : आप हमारे यहां के रिश्तेदार हैं न उसी हक से हम खड़े हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं- एक हैं आप रामेश्वर पासवान जी और दूसरे थे छेदी पासवान जी, दोनों अभी बाहर हैं नये कोई इंडक्ट होनेवाले हैं क्या ?

श्री रामेश्वर पासवान : सभापति महोदय, हमारी बात सुन लीजिए नेता में वो गुण चाहिए, लीडरशिप वह चाहिए, जो कमांडर इन चीफ होते हैं कौन आदमी कहां काम करेगा, वह चयन करके वहां पोस्ट कर देते हैं। यह कभी नहीं कि किस मोर्चा पर कौन काम करेगा, नेफा पर करेगा कि लद्दाख पर करेगा वह चयन करके उन्होंने इस प्रकार की बात को पोस्ट किये हैं इसलिए फख्र है। ये फख्र है चाहे रामेश्वर पासवान हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे छेदी पासवान हो, बड़े-बड़े इस प्रकार की बात कि इस प्रकार का एक डिस्क्रियेशन है और उसका चयन का एक सोच है और चिंतन है कि कौन हमारा कार्यकर्त्ता, कौन हमारा कमांडर किस मोर्चा पर काम करेगा वो काम करे। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से हम महोदय- अच्छी बात है। महोदय, हम ये कह रहे थे कि कृषि रोड मैप और ये जो शिक्षा की बात कर रहे थे तो शिक्षा की बात में तो और बृहत् अतुलनीय है, अभूतपूर्व है इसप्रकार की तुलना देश में नहीं है, लोग नकल कर रहे हैं इस प्रकार का कि बिहार का हम रोल मोडल करें। आज सुनकर के आश्चर्य होगा कि गोवा भी कहता है कि हम बिहार का रोल मोडल करेंगे, बिहार का नकल करेंगे। गोवा- आज पेपर में पढ़े होंगे हमारे सिद्दिकी साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, पढ़ते बहुत हैं। गोवा कह रहा है, महाराष्ट्रा कह रहा है, कर्नाटका तो फोलो कर ही लिया।

क्या थे, कहां पहुंच गये फिर भी आपको इस प्रकार दिखायी नहीं पड़ता है तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसे विद्वान, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस प्रकार के दृष्टिगोचर कर देते हैं तो फिर किससे आशा और उम्मीद करे इस देश और इस प्रांत के लोग। महोदय, आपके ग्रामीण कार्य विभाग, रोड की बात कर रहे थे इतना तक हो गया कि कोई ऐसा बसबुट्टी खासकर के ढाई सौ की आबादी, पहले आपके प्रधानमंत्री सड़क योजना से इस प्रकार के ५०० से लेकर के ९०० तक की बात करे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बात को लेकर के अभी जो भी है ढाई सौ, पांच सौ की आबादी जो डिस्कनेक्टेड हैं उन सभी को संपर्क पथ से जोड़ रहे हैं और खासकर के उस टोले को जो महादलित लोग हैं, दलित लोग हैं जिनको इस प्रकार की जो कभी नसीब नहीं हुआ था, आपके रेडियो, टी०वी०, स्कूल, शिक्षा वो समझिए उनके गांव में इस प्रकार पहुंच रहा है.........क्रमशः।

श्री रामेश्वर पासवान : ... क्रमशः ...

तो शिक्षा को ले करके टोला टोला, मुहल्ला मुहल्ला, आंगन से शुरू, आंचल से शुरू ले करके विश्वविद्यालय तक पहुंच गये हैं इसलिये यह अतुलनीय है किसी प्रदेश से हमारी तुलना कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम करें । लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या कारण है, हम कभी नहीं कहेंगे फॉलो करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं कहे कि हम दूसरे राज्य का फॉलो करेंगे । स्टडी करने की बात है कि हम जानकारी करें हम, वो कहां हैं हम कहां पहुंचे हैं । गुजरात भी पीछे हो रहा है । वो तो अब बिल्कुल अपने को इनफीरियर फील कर रहे हैं कि हम कहां हैं, क्या होगा ? वे सोच में पड़ गये हैं । ऐसी हालत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि फॉलो कहीं कुछ कर रहे हैं । आज आपके रोड की बात, हुजूर इस प्रकार की बात है, प्रसंग में बात आ गयी एक लछुआर है, जैसा कि अभी कह रहे हैं, वो लछुआर जमुई इलाके से ले करके पूरा जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहां पर कि एम0सी0सी0 की शरणस्थली मानी जाती है झारखंड से ले करके यहां तो वैसी हालत में उस जंगल में भी रोड के लिये हमारे माननीय मंत्री प्रभारी आदरणीय भीम सिंहजी हैं, जी, तो वैसी हालत में वही भगवान महावीर की जन्मस्थली मानी जाती है, ऐसे वैशाली कहते हैं लेकिन गजेटियर उठाकर देखने से 1820 से ले करके देखते हैं तो भगवान महावीर का जन्मस्थान वही लछुआर माना जाता है और लछुआर में अभी उस दृष्टिकोण से हमारे जितने जैनी लोग हैं लाखों लाख लोग एक वर्ष में आते हैं, कम से कम एक लाख लोग और वो जंगल जाकर वो भगवान महावीर की पूजा करते हैं और हर मौसम में, ये नहीं कि एक मौसम में हर मौसम में जाते हैं तो वहां रोड, जिस समय हम पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर थे 1970 की बात मैं कर रहा हूं, एक रोड बनाये थे लेकिन माननीय मंत्री प्रभारी जो हमारे ग्रामीण कार्य मंत्री हैं उनसे हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि उस रोड को कम से कम एक बना दें जो 12 किलोमीटर की रोड है वो दो दृष्टिकोण से ठीक होगा, हमने पहले ही कहा कि हमारे यहां पर्यटन और आपके कृषि ये दोनों रह गया तो पर्यटन के दृष्टिकोण से, टूरिज्म प्वायंट आफ व्यू से वो बहुत बेस्ट प्लेस होगा, एक इनकम का जरिया भी होगा, लोगों का रोजी रोजगार जो मिलता था वहां पर क्षेत्रीय मजदूरों को वह बंद हो गया है । रोड की खराबी की वजह से कुछ लोग लॉ ऐंड ऑर्डर की बात करते हैं,बाकी जंगल है, एम0सी0सी0 का कुछ न कुछ कहर है, ये इसमें पूरे देश की बात है, आज हमारे बिहार में ही नहीं पूरे राष्ट्र में है, पूरा विश्व इससे चिंतित है कि नक्सलवाद को ये कैसे हम रोकें । उसी सिलसिले में ये ग्रसित है उससे लेकिन हम माननीय मंत्री से कहेंगे कि इसको कम से कम रोड बना दें, जिसको हमने शुरूआत किया था वो रोड टूट फूट जाने से टूरिज्म का आना बंद हो गया और उससे जो कुछ घटनाएं भी घट जाती हैं,लोग रहते हैं तो घटनाएं भी घट जाती हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं उस प्रकार से जाने में उनको दिक्कत होती है । तो उनसे मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से कि वो अविलम्ब उसको बना दें जिससे और आगे चल करके

जहां पर कुंडिल ग्राम की बात करते हैं, भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है, वो एक लछुआर जगह है जहां पर एक बार आप सभी जितने जनता दल के लोग थे मोरारजी देसाईजी के नेतृत्व में वहां मीटिंग किये थे, लछुआर में ही और वही लछुआर महोत्सव का, खास करके भगवान महावीर के अनुयायी जितने लोग हैं जैनी लोग, वे सभी अनुरोध किये हैं कि वहां लछुआर महोत्सव मनाया जाय । इसलिये हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी को, प्रभारी माननीय मंत्रीजी के माध्यम से भी कि वो एक बार कम से कम लछुआर को देख लें जैनिज्म के दृष्टिकोण से तो जैन सर्किट भी उभरेगा, टूरिज्म भी उभरेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सभी लोगों को खास करके आवागमन की जो एम0सी0सी0 का जो इस प्रकार गढ़ बना हुआ है उससे भी राहत मिलेगी । सभापति महोदय,आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, हमको तो लगता है एक एक बात पर कहां कहां किसकी बात चर्चा करूं, स्वास्थ्य जहां पर कि लोग जाते थे हॉस्पिटल या हमलोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाते थे तो मरीज की जगह पर कुत्ते नजर आते थे । वो बेड पर, अभी नहीं,सम्राट बाबू, कम से कम दिन में बोल रहे हैं, रात में नहीं, दिन में देखिये, आज की बात, आज तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्रीजी का ये आदेश है कि चौबीसों घंटा, सिकंदरा में तो और नहीं, चौबीसों घंटा आपके, जो बिजली नहीं है,नहीं बिजली नहीं, बिजली तो बहुत कम है बिजली तो आपलोगों की वजह से इस प्रकार की बिजली नहीं मिल रही है तो वहां बिल्कुल लोग चौबीसों घंटा लोग बैठते हैं, कोई न कोई डॉक्टर रहते हैं, कोई न कोई स्टाफ रहता है, इलाज होता है । आज की चर्चा कर रहे थे जमुई की चर्चा । उस चर्चा की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी कल कर चुके थे जमुई की बात, मैं उसमें कुछ बात और जो जानता हूं मैं कह देना चाहता हूं, चूंकि प्रसंगवश आ गया है, प्रतिपक्ष के नेता भी कल बोले मेरा क्षेत्र है और क्षेत्र के बोर्डर पर घटना घटी है । वो घटना घटने के बारे में सुन चुके पेपर में पढ़ चुके, घटना घटने के बाद सिकंदरा के रास्ते जमुई पड़ता है, रिलेटिव के यहां जा रहे थे, जमुई के रास्ते में सिकंदरा है, सिकंदरा हॉस्पिटल में ले गये वो लोग, ठीक साढ़े आठ बजे, आठ बजे घटना घटी, साढ़े आठ बजे लोग पहुंचे, डॉक्टर मौजूद थे, वो लोग कहे कि इलाज इस प्रकार की बात हो गयी है देखे, देखने तक भी नहीं दिये, वो बोले हमको जमुई जाना है, जमुई ले जायेंगे, यहां इस प्रकार की बात, गोली नहीं, वो बोले कि गोली हम यहां नहीं निकाल सकते हैं लेकिन गोली निकालना होगा तो, उस समय मूड़ी लटकाये जीवित थी, मूड़ी लटकाये बैठी थी और वैसी हालत में अगर वहां यहां हम ये करते हैं तो देर हो सकती है लेकिन आप कहिये तो हम इलाज शुरू करें । वे लोग इलाज करने नहीं दिये और तुरत उनसे ज्यादा बात नहीं करके पुलिस का इन्फार्मेशन भी वहां के लोग जो थे, डॉक्टर भी पुलिस को इन्फार्मेशन देने के लिये टेलीफोन किये, टेलीफोन उठाया नहीं, ये वहां के दारोगा जो हैं वो कुछ नेगलीजेंसी किया, उदासीनता बरते हैं लेकिन डॉक्टर, हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं, वो टेलीफोन उठाये नहीं, कभी एंगेज, कभी रिंग करके उठाये नहीं

फिर पत्रकार एक है, पत्रकार को कहा गया कि पत्रकार जाकर आप खबर कर दीजिये, वो भी टेलीफोन से कहा जो सामने डॉक्टर थे, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका भी टेलीफोन रिसीव नहीं किया । रिंग करे लेकिन उठाया नहीं, कभी एंगेज लगे, कभी रिंग करे, 15 मिनट तक यही नजारा चलते रहा लेकिन दारोगा वहां पर कोई उठाया नहीं और इसके बाद वो नोटिस नहीं लिया । लास्ट में वो जो मरीज थे और जो बर्णवालजी थे वो ले करके जमुई चले गये, जमुई में जा करके इलाज जो हुआ वह जानकारी है और इसके बाद वहीं केस, एफ0आई0आर0 लॉज हुआ और इसके बाद जो है । तो जितना करना चाहिये और जो घटना घटी वो हमारे क्षेत्र का बोर्डर पड़ता है, लखीसराय और शेखपुरा का दोनों तीनों का बोर्डर पड़ता है, बोर्डर के रास्ते में, तो वैसी हालत में घटनाएं जो हुई, ये जो कहा जाता है लोग जो इस प्रकार की बात बोले क्या हुआ, नहीं हुआ वह अभी अनुसंधान के क्रम में है लेकिन जो उन्होंने देखा और सुना, इस रूप में सभी लोग जो वहां पर कहते हैं इस प्रकार की घटना कोई भी निंदा कर सकता है, हमारे मुख्यमंत्रीजी काफी निंदा किये, सभी प्रकार के अनुसंधान तुरत डी0जी0पी0 को आदेश दिये, जांच हो रही है वो बात होगी लेकिन एक बात जरूर है, हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि वहां के खास करके थाना प्रभारी जो नोटिस लेना चाहिये था उसमें उदासीनता वो बरता है, उसके अनुकूल थोड़ा ऐक्शन होना चाहिये और हमलोग भी टेलीफोन करते हैं तो जल्दी जो इस प्रकार की बात होती है तो उठाते नहीं हैं । उठाते भी हैं, किसी प्रकार का कहीं न्यूसेंस क्रियेट हो जाता है, कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं या वैसे अपराधी लोग होते हैं, उस प्रकार की चर्चा करते हैं तो वो सीधे अपराधी को कह देते हैं और अपराधी फिर टेलीफोन करता है । सही बात हम ही लोग बोल सकते हैं, आपलोग सही बोल नहीं सकते हैं । सही बात इस प्रकार की बात जो है ये बात है कि सभी लोग सभी खराब नहीं होते, सभी अच्छे नहीं होते । है, वो इकरार करते हैं कि इस प्रकार की बात, घटनाएं घटती हैं तो ऐसी हालत में उसके सुधार की बात होनी चाहिये और वैसे व्यक्ति को जो आवश्यक दंड होना चाहिये या कार्रवाई होनी चाहिये उसके अगेंस्ट में बात होनी चाहिये ।

सभापति(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : कंक्लूड करें ।

श्री रामेश्वर पासवान : जी । अब बिल्कुल आखिरी बात है सभापति महोदय,मैंने कहा इर्रीगेशन की बात, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात वो इस प्रकार की बहुत वृहत् है लेकिन इर्रीगेशन के बिना न कृषि रोड मैप कर सकते हैं, न हम और आप रह सकते हैं ।

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून ।

बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता है । आ रहा है समझिये अब स्कारसिटी आफ ड्रिंकिंग वाटर जो हो जायेगा इसके लिये हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इर्रीगेशन के मामले में आपको पहले ही सावधान हो जाना पड़ेगा । बिना इर्रीगेशन के आप न ऐग्रीकल्चर रोड मैप

को सफल कर सकते हैं और न हमको और आपको जिंदा रख सकते हैं । इसलिये पी0एच0ई0डी0 का जो काम हुआ, हमलोगों को 2006 में ही प्रत्येक पंचायत में तीन मिला था, अभीतक वह फुलफ्लेज्ड के रूप में गाड़ा नहीं गया । अभी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने पांच-पांच चापाकल की घोषणा किये हैं, बड़ी खुशी हुई ।

... क्रमशः ...

श्री रामेश्वर पासवान, क्रमशः- कि इस प्रकार के हमलोगों को इस प्रकार के अपने पंचायत,अपने क्षेत्र में कुछ देना पड़ेगा,तो वह इस प्रकार की बात होगी और एरिगेशन के मामले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने २००८ में ही कुंड घाटी जलाशय योजना है,उसका शिलान्यास किये थे, पूरा होने की घोषणा २०१० को ही हो गयी थी,आज २०१२ जा रहा है,वैसी हालत में एक जंगल विभाग के जैसे दुर्गावती का हुआ, उसी तरह से वह लटका, वैसी बात नहीं है,सब कुछ हो गया लेकिन फौरेस्ट डिपार्टमेंट को लिबरल होना चाहिए, इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं,जंगल विभाग के खास करके जो नोटिफिकेशन हो, रोड कन्सट्रक्शन हो या एरिगेशन के मामले में कुछ हो, तो फौरेस्ट डिपार्टमेंट जो बिल्कुल भारत सरकार के अधीन है, जो केस करता है..........(व्यवधान)

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह):- अब आप समाप्त करें।

श्री रामेश्वर पासवानः- उसके लिए कुछ पहल करें,ऐसा रास्ता निकालें कि हमारी सरकार की बात मानें,यह नहीं कि अपने मन से जहाँ कुछ हो,तो योजना भी खटाई में पड़ जायगी, हमलोग रोडमैप क्या बनायेंगे, मैप पर ही रह जायेंगे, एरिगेशन की सफलता नहीं होगी। इसलिए हम जरुर यह कहेंगे इस रुप में पहल होनी चाहिए लेकिन एक बात जरुर है कि जो इन्होंने सपना देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने,वे उसमें पीछे हटने वाले नहीं है,वे उसको साकार करेंगे। मेरा एक आखिरी लव्य है किः

"अगर चल करके थके भी,तो रुके नहीं,क्योंकि मंजिल अभी बहुत बाकी है,
अभी तो बिहार संभाला है लेकिन दिल्ली अभी बाकी है।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह):- माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हाः- सभापति महोदय, मैं विनियोग विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सत्तापक्ष का विधायक हूं लेकिन मैं विधायक की हैसियत से नहीं, आज मैं बिहारी की हैसियत से इस सदन में बात रखना चाहता हूँ और जो बात रखना चाहता हूँ वह सदन में नहीं रहेगी बल्कि सदन के बाहर जायगी और इस सदन में जो बात होती है, वह इसी सदन में नहीं रहता है बल्कि सदन के बाहर पूरे राज्य में,पूरे देश में जाता है। सभापति महोदय,हम सब आज इस बात पर विचार करेंगे और सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि बिहार बढ़ेगा, तब हम बढ़ेंगे और जितने दल के लोग हैं,दल भी बढ़ेगा। सभापति महोदय,विनियोग विधेयक पर प्रतिपक्ष के विद्वान माननीय सदस्यों ने विचार रखें हैं और इस सदन में हमारे नेता बैठे हुए हैं,उनका जवाब हमारे नेता देंगे,मैं अपनी ओर से इस सदन को कहना चाहता हूँ कि जंगल मांगे आजादी,पहाड़ मांगे आजादी,नदी मांगे आजादी,पशु मांगे आजादी,किसान मांगे आजादी, सभापति महोदय, इन सारे मांगों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने कृषि रोडमैप बना करके जो गाँधी, लोहिया, जयप्रकाश जी का सपना था,उस सपना को पूरा करने के लिए बजट बनायी है और उस बजट के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलूंगा,इसलिए नहीं बोलूंगा कि वह ऑकड़ा का चीज है, ऑकड़ा में मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं सदन में कहना चाहता हूँ माननीय सदस्यों से कि यह सदन जो है,वह वाक्ययुद्ध का है,मलयुद्ध का नहीं है। यह खुशी की

बात है कि एक साल से ज्यादा समय से, मैं इस सदन में आया हूँ,पहले हम ४४ साल पहले मैं आया था लेकिन नीचे नहीं आया था,उपर आया था,जिस कुर्सी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं,उस समय महामाया बाबू जिगर के टुकड़े बैठे हुए थे,जिस कुर्सी पर मोदी जी बैठे हुए हैं हमारे सम्मानीय नेता,उस समय उस कुर्सी पर माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बैठे हुए थे। बंधुओं, सदस्यों, उस समय कर्पूरी ठाकुर विरोधी दल के ५९ साल पहले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सारे अफसरों को,जो अफसर घूस लेता था, उस घूस लेने वाले अफसरों को, उस समय के राजस्व मंत्री कृष्णबल्लभ सहाय हुआ करते थे, कृष्णबल्लभ सहायक से कहा गया था कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं,तो उसको चौराहे पर लाकर पीटने का काम कीजिये लेकिन हमारी सरकार ने उस समय आवश्यकता थी,परिस्थिति थी कि उन्होंने ऐसा बोला लेकिन हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है,उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमारी सरकार ने हमारे नेतृत्व में एक कानून बनाया है,वह कानून जो है,वह है प्रखंडों में अवधि तय किया हुआ है कि अगर उस अवधि में अफसर काम नहीं करेंगे, तो उस अफसर को दंडित किया जायेगा, यह काम हमारी सरकार ने किया है और मैं पहले भी बोला, चूंकि दॉत में दर्द है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी ओर से ....(व्यवधान)

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह):- अब हो गया। मा० सदस्य सुरेन्द्र बाबू बैठ जाइये।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हाः- हम समाप्त कर रहे है सभापति महोदय। यह सरकार डाक्टर लोहिया, पंडित दिनदयाल उपाध्याय और लोकनायक जय प्रकाश नारायण के सपनों को पूरा कर रही है। पंडित दिनदयाल जी ने कहा था कि "हर हाथ को काम,हर खेत को पानी", डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि "जब तक भूखा इंसान रहेगा,धरती पर तूफान रहेगा" और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था "संपूर्ण क्रांति का",सारे कामों को यह सरकार कर रही है इसलिए मैं विनियोग विधेयक पर बोल रहा हूँ और जो विनियोग विधेयक है, जो हमारे मोदी जी, जो हमारे नेता ने बजट पेश किया है इस सदन में, वह रोजगार बढ़ाने वाला बजट है, निवेश लाने वाला बजट है, गरीब, आम जनता को कल्याण करने वाला बजट है और यह बजट विकासन्मुखी है, रोजगारन्मुखी है।

क्रमशः

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा (क्रमशः) : और हमारी सरकार हलधर किसान के लिये भी, क्षतगर किसान के लिये भी, बंगलागर किसान के लिये भी सभी तरह के किसानों के लिये बजट बनाया है, हमारे राज्य में जो हलधर किसान है, उसके बारे में भी हमारी सरकार ने सोचा है । जो क्षतगर किसान हैं, उस के बारे में भी हमारी सरकार ने सोचा है और जो बंगलागर किसान हैं, उस के बारे में भी हमारी सरकार ने सोचा है और जो नामगर किसान हैं, उस के बारे में भी हमारी सरकार ने सोचा है । महोदय, यह बिहारी की बढ़ोत्तरी और सारे लोगों की बढ़ोत्तरी का प्रमाण है । इन्हीं शब्दों के साथ, हमारी बारी लंबी थी लेकिन कष्ट के कारण मैं संतुष्ट नहीं हूं, कभी समय आयेगा तो मैं बोलूंगा।

सभापति (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह) : माननीय नेता, विरोधी दल ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक के दिन ही एहसास होता है कि इस सदन की सार्वभौमिकता है और विधायकों की पूछ है । यूं तो सारे विभाग के डिमांड्स एक तरह से पास हो गये इस हाउस से। अब विनियोग में ऑथोराईजेशन लेने के लिये हमारे वित्तमंत्री आये हैं । मगर विनियोग विधेयक पर भी मैं अक्सर चर्चा इस वजह से कर दिया करता हूं कि विनियोग विधेयक का भी हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जब आप के डा०जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने यह कहकर विरोध किया था कि जो करनीय काम है, वह न करे, और अकरनीय काम को करने की आदत जिस सरकार को पड़ गई और जो सरकार असक्षम हो, सदन द्वारा लिये गये पैसे को खर्च करने में तो उस को क्यों कर पैसा देना चाहिए ? हमारा यह एक बुनियादी सवाल है । जिस दिन थर्ड सप्लीमेंटरी वित्त मंत्री जी ने सदन में पुट किया था, उस दिन मैंने कुछ बुनियादी सवाल उठाया था, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यह तो विनियोग का मैटर है, विनियोग में आप लाईयेगा। मैं हल्के-फुल्के ढंग से उस को दुहरा रहा हूं ।

महोदय, जो १६.०३.२०१२ तक का वित्त विभाग ने अधिकृत खर्चा का जो व्यौरा दिया है,वह निम्न प्रकार है :-

स्टेट प्लान में ५२.७२ परसेंट १६.०३.२०१२ तक और सेंट्रल स्पॉसर्ड प्लान स्कीम में खर्च हुआ ४५.७१ परसेंट और सेंट्रल प्लान स्कीम में ३५.३७परसेंट । अब कौन-सा करिश्मा होगा और कौन-सा एंगिल लगेगा, जो रेस्ट पैसे हैं,वह इस दो हफ्ते में खर्च हो जायेगा और जब सत्ता पक्ष के विधायक बोलने लगते हैं तो बोलते हैं कुछ और जब क्वेश्चयन करते हैं, आज ही, मैं एक तरह से आभार व्यक्त करता हूं मुख्य मंत्री के प्रति कि मुख्य मंत्री जी ने उस बात को इतनी गंभीरता से संज्ञान में लिया, जो माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी का प्रश्न था, जहां टूटना है, जहां बनना है, आज मार्च के महीने में किस तरह से खर्च हो रहा है, हम भी सरकार में रहे हैं, सरकार में जो हमारे अधीनस्थ लोग होते हैं, उन के लिये मार्च एक गोल्डेन पीरीयड है और वे चाहते हैं कि इस गोल्डेन पीरीयड में जितना पैसा खर्च हो सके, हो जाय । महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि आज बैठे-बैठे देख रहा

था कि मुख्य मंत्री जी बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया, डेवलपमेंट कमीशनर को जांच करने का आदेश दिया।

महोदय, मैं इस वजह से आया कि जो सेंट्रल प्लान स्कीम्स है, इस में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उस के खर्च की क्या स्थिति है ? इस वजह से कि जब यह हाउस देता है तो यही हाउस मालिक है हिसाब लेने का । भले आप हिसाब ले या न लें । मगर जब हम मालिक की हैसियत से आप को पैसा देते हैं, ऑथोराईज करते हैं तो हम हिसाब-किताब मांगेंगे जरूर । मगर सत्ता के मद में आप अपार बहुमत में इतने मदांत हैं कि हमारे वाजिब सवालों को भी आप कहते हैं १५ साल । कितना दिन ? महोदय, अब आ जाईये । सेंट्रल प्लान स्कीम, रूलर डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट, १६.०३.२०१२ तक इसकी उपलब्धि है जीरो परसेंट । उस के बाद माईनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट - जीरो परसेंट । फूड एण्ड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट-जीरो परसेंट । बोलेंगे वित्त मंत्री जी सेंट्रल प्लान पर। यह मेरा नहीं है, वित्त विभाग ने जो व्यौरा दिया वह है यह ।

अब महोदय, आ जाईये । डिपार्टमेंट वाईज ब्रेक-अप डिटेल स्टेट प्लान ।
इनर्जी डिपार्टमेंट, खर्च किया - २८.७१ परसेंट ।
प्लानिंग एण्ड डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट, खर्च किया - १०.१ ७परसेंट ।
पंचायती राज डिपार्टमेंट, खर्च किया - २९.७८परसेंट ।
अरबन डेवलप्मेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट, खर्च किया - १४.३ ७परसेंट ।
इनफॉर्मेशन एण्ड टेकनॉलोजी डिपार्टमेंट, खर्च किया - ८.४३ परसेंट ।

यह तो हो गया स्टेट प्लान का । अब महोदय, सेंट्रल स्पॉसर्ड प्लान स्कीम । इसकी स्थिति और बहुत खराब है ।

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट - इसको मिला बजट एस्टीमेंट का ९.१८, रिभाईज्ड हुआ १५.१४ और खर्च - जीरा परसेंट ।

लेबर रीसोर्स डिपार्टमेंट - इसको मिला बजटरी प्रोविजन- ६.९०, रीभाईज्ड हुआ ६.९० और खर्च हुआ- १०.२९

उसके बाद होम डिपार्टमेंट - जीरो परसेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट - जीरों परसेंट, सुगर केन एण्ड इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट - ९.८४ परसेंट, साईंस एण्ड टेकनोलॉजी डिपार्टमेंट - जीरो परसेंट ।

अब आप बतायें । हमलोग भी चाहते हैं कि केन्द्र ज्यादा-से-ज्यादा पैसा दे बिहार जैसे अविकसित राज्य को विकसित होने के लिये । हमलोग भी यह मांग करते हैं, हमलोग राजनीति के तहत मांग नहीं करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए । हमलोग भी मानते हैं कि पावर सेक्टर में राज्य सरकार को और मदद मिलनी चाहिए । मगर जो पैसा मिल भी रहा है, उस की उपलब्धि देख कर आप की राशि क्यों बढ़ायी जाय ? अब यह विचारणीय प्रश्न है, अगर यह हमारे समय का रहता, १५साल का तो आज प्रिंट मीडिया में यह लीड न्यूज फर्स्ट पेज पर बनता कि बिहार सरकार सेंट्रल स्पौंसर्ड स्कीम का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है । पंचायती राज का खर्च नहीं कर पा रही है, वगैरह वगैरह ।

क्रमश :

टर्न-17/सत्येन्द्र/28-3-12

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी(नेता विरोधी दल)(क्रमश:) महोदय,मैं फिर आ जा रहा हूँ,अब चूंकि मैंने बुनियादी सवाल उठाया था महोदय,आप भी संसदीय अभिरूची रखने वाले हैं,मैं बार-बार कहता हूँ कि जो लेखाकार हैं,उनका रिपोर्ट अंतिम दिन ही क्यों ले होगा,अगर हम उस पर बहस करना चाहें या कराना चाहें,हम कैसे करायेंगे। उस दिन हमारे विद्वान संसदीय कार्यमंत्री कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष को मालूम नहीं है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर से ले होता है,अरे राज्यपाल के द्वारा ही आप मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं,मगर कौन नहीं जानता कि राज्यपाल हेड ऑफ दी स्टेट होता है,मगर काम करता है बाई द एडवाईस ऑफ द कैबिनेट,अब जिस सरकार में एक महीना से सी0ए0जी0का रिपोर्ट ले करने के लिए मिला हो,वो अंतिम दिन आये, यह परम्परा कतई अच्छी नहीं है। अब महोदय,2011 में खर्चा हुआ 10553 करोड़,इसमें 3 हजार करोड़ मामले जो ए0सी0 और डी0सी0 बिल के हैं,आपको याद होगा शुरूआती दौर में जब ए0जी0 ने रिपोर्ट ले किया था तब लोगों ने कहा कि इसमें तो 2000 से लेकर 2005 तक का भी मामला है, उस वक्त 2000 से लेकर 2005 तक का मामला कितना था उसको हटा दीजिये और अभी का कितना मामला है,आपको जानकर ताजूब होगा कि डी0सी0 बिल की तायदाद राशि में जो जमा करनी है वो 25335 करोड़ से भी ज्यादा हो गयी तो आप बतलाईए कि आपका बैड फायनेंसियल मैनेजमेंट या गुड फायनेंसियल मैनेजमेंट। आप अगर यह बतलाईए कि आप जो राशि लेते हैं और जो वादा करते हैं सदन में आप उस पर खर्चा करते हैं या पार्किंग करते हैं या फिर आप इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जमा करते हैं,सोसायटीज में जमा करते हैं,एजेंसी में जमा करते हैं,बैंक में जमा करते हैं बगैरह-बगैरह।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय,मैं चूंकि विस्तार से आज इस वजह से भी नहीं जाना चाहता हूँ अगर आप बैठ गये हैं तो मुझको लगता है कि समय मिलेगा पर्याप्त। महोदय,मुझको कभी कभी ताजूब होता है,हम भी जानते हैं,अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है,अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है,मगर जो सरकार होती है वो सरकार संदेश देती है अपराधियों की बीच,मनबढुओं के बीच,सामंतों के बीच,गरीबों के बीच कि वह किसकी सरकार है,वो संदेश देती है सरकार कि वह किसी सरकार है। आज अपराध किनके पर हो रहा है,आज किनका रेप हो रहा है,आज कौन मारे जा रहे हैं,आज कौन सताये जा रहे हैं,कमजोर तबके के लोग हैं और आज आपने संदेश दिया, चाहे आप जितना भी कहें कि

साहब हमने एनेक्सर-1 को ये कर दिया,हमने महादलित के लिए ये कर दिया,मगर आज 98 क्या 99 फीसदी अगर क्राईम का भिक्टिम प्रोफाईल आप देखेंगे तो ये कमजोर तबके के लोग हैं,कमजोर तबके के लोग हैं, इसका मतलब हुआ यह संदेश चला गया सरकार का कि मन बढुओं का राज है, सामंतों का राज है और जुल्मियों का राज का और जुल्म करने वालों का कोई रोकटोक नहीं है। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति के तहत नहीं,आज नवादा की दो महिला हमारे पास आयी और रोने लगी पैर पकड़ कर के, आपके यहां क्यों नहीं जाती है,इस वजह से उसका जो यह दरख्वास्त है, मैं इसको दे दूंगा मोदी जी कहेंगे मुख्यमंत्री,दिल दहला देने वाला यह दूसरा नमूना है। मैं समाज की अत्यंत ही कमजोर वर्ग..

श्री सुशील कुमार मोदी(उपमुख्यमंत्री):आज गृह विभाग का वजट है क्या, आप इस पर बोलियेगा,यह आज का विषय है क्या? आप इसको अलग से उठाईए।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी(नेता विरोधी दल):मोदी जी,आपका विनियोग का भाषण भी हम उलट पुलट करते रहते हैं। विनियोग में सभी विभाग जिसका डिमांड पास हो गया और आप विनियोग में आये औथोराईजेसन के लिए हमको हक है बोलने का मैं अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोलुंगा। मैं समाज की अत्यंत कमजोर वर्ग की यह बढ़ई जाति की औरत है,12 साल की इसकी लड़की का होली के दिन ही गांव के लोग अपहरण करते हैं। यह दिन भर खोजती रहती है,दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है और लाश मिलती है बयान है इसमें, मैं बयान नहीं कर सकता वो लोग पकड़ाये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है मगर मैं यह आवेदन इस बात का उदाहरण है कि बड़े लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे मैनेज करते हैं,बड़े लोग बड़े बड़े पदाधिकारियों को कैसे मैनेज करते हैं, हम इस वजह से सिर्फ उल्लेख कर दिया महोदय मैं चूंकि इस बजह से बोल रहे हैं कि जो भारत सरकार है महोदय इसमें 22 जातियां अनु0जाति में आती है। ठीक है, महोदय 22 जातियां अनुसूचित जाति में आती है,महादलित सरकार ने बनाया 21 जातियों का मेरा कोई विरोध नहीं है मगर अनुसूचित जाति के लिए जो अरबों रू0 आते है राज्य सरकार को वो सिर्फ इसी एक जाति में क्यों नहीं खर्चा होता है। जब आपने 21 जातियों को महादलित बना लिया और भारत सरकार अपने सेंटर ऐसपौंसर्ड स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए जो राशि भेजती है वो एक मात्र बचा हुआ अनुसूचित जाति पासवान में क्यों नहीं खर्च होता है, तो अब जो भी राजनीति हो हम उससे इतफाक नहीं करते हैं मगर चलिये मैंने तो

पहले ही कहा था कि ए0बी0सक्सेना ने मुसहर जातियों की अर्थव्यवस्था जिंदगी रहन सहन देखकर एंज ऐ ग्रामीण सचिव जो अनुशंसा की थी वो अब अभी विभिन्न योजनाओं के काटकर लागू की जा रही है। महोदय,मैं अंत में यही कहूंगा भले आप मानो या मानो, भले आप कहो कि सुशासन है, भले आप कहो कि राम राज्य है,भले आप कहो कि हमसे अच्छा शासन किसी का है ही नहीं,भले आप कहो कि हमारे पद चिन्हों पर ओबामा भी चल रहा है और अमरीका भी चल रहा हैं और मनमोहन भी चल रहे हैं;यही न खुश। जब आप इतने खुश हो तो हाथ मत पसारो, इतने खुश हो तो मैं फिर मैं इतफाक नहीं करता, उनकी राजनीति से नरेन्द्र मोदी की राजनीति से मैं इतफाक नहीं करता मगर कम से कम उसके तरह पुरूषार्थ तो पैदा करो। महोदय,आज इन्दिरा आवास योजना,मनरेगा योजना,एन0आर0एच0एम0 योजना की जो गड़बड़ियां हैं(क्रमश:)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता, विरोधी दल: क्रमशः मैं अभी फैन नहीं हुआ हूं । यह भ्रम में मत रहिएगा और यह हम जानते हैं कि जो लोग आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं जब नरेन्द्र मोदी आगे आएंगे तो आप ही नीतीश जी का पैर भी खींचेंगे, यह भी हम जानते हैं । यह हम जानते हैं । महोदय, फिर भी जो राशि सेंट्रल स्पौंसर्ड स्कीम का, सेंट्रल प्लान का, स्टेट प्लान का ठीक ढंग से खर्चा नहीं कर सकती है सरकार, मार्च लूट कराती है, पार्किंग करती है, बैंक में जमा करती है पैसा और उस दिए गए पैसा से अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाती है बल्कि इसी पैसा के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता है । इसलिए इनको एक पैसा नहीं ऑथोराइज करना चाहिए खर्चा करने के लिए । थपथपी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब सरकार का उत्तर ।

सरकार का उत्तर

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, विरोधी दल ने अभी सी0ए0जी0 की रिपोर्ट का हवाला दिया है, और कहा है कि अंतिम दिन वह रिपोर्ट की जाती है और उस पर चर्चा करने का अवसर भी मिलता है । व्यवधान।

अध्यक्ष : शांति। शांति ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्यमंत्री: आप तो इतने पुराने सदस्य हैं और नियमावली आपको मालुम है। आप लोक लेखा समिति के चेयरमैन रहे हैं । कभी भी महालेखाकार की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होती है, यह तो मुझे नहीं मालुम है कि कोई प्रावधान इस प्रकार का.. व्यवधान.. हुआ है और इसी सदन में हुआ है तो क्या कहता है नियमावली, कि लोक लेखा राज्य के विनियोग और वित्त लेखाओं तथा उनपर नियंत्रक महाअंकेक्षक के प्रतिवेदनों पर सभा में विमर्श नहीं होगा, जब तक कि नियम 239 के अधीन ऐसे लेखाओं प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित न कर दिया जाए । तो यहां तो जब महालेखाकार की रिपोर्ट रखी जाएगी, तब लोक लेखा समिति के पास जाएगा और लोक लेखा समिति जब प्रतिवेदन देगी, तब न विचार होगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता,विरोधी दल: 239 के तहत कोई भी माननीय सदस्य हाउस में डिमांड कर सकता है महालेखाकार के रिपोर्ट पर बहस करने के लिए ।

टर्न-18//28.3.2012/बिपिन ..

श्री सुशील कुमार मोदी,उप-मुख्यमंत्री: क्या चीज की बहस के लिए !

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता,विरोधी दल: महालेखाकार के रिपोर्ट पर ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप-मुख्यमंत्री: अब आप ही इसका नियमन देंगे ! अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आज तक नहीं मालुम है कि रिपोर्ट ले' होती है उस पर कहीं चर्चा, आज तक कहीं रिपोर्ट पर चर्चा हुई है क्या !

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता,विरोधी दल: अभी तो लोक सभा में चर्चा हुई है ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप-मुख्यमंत्री: कहां चर्चा हुई है ! चर्चा कहां हुई है ! रिपोर्ट पर चर्चा हुई है क्या ! व्यवधान ।

अध्यक्ष : शांति । शांति ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप-मुख्यमंत्री: इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो महालेखाकार का प्रतिवेदन है वह जब भी हम रखे हैं यहां सदन के अंदर, उसपर तत्काल कोई चर्चा करने का प्रावधान नहीं है, और वहां भी जो चर्चा हुई है, वह कोई लोक लेखा समिति रिपोर्ट पर नहीं हुई है, जो उसका अंश लीक किया गया, जो लीक हो गया, अखबारों में आया है, उसके संदर्भ में विपक्ष ने दूसरे तरीके से मामले को उठाया था, और अध्यक्ष महोदय, बार-बार नेता, विरोधी दल और विपक्ष के द्वारा इस बात को उठाया जाता रहा है कि सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही है,और वित्तीय वर्ष के अंत में पैसा खर्च होता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले भी कहा, कि यह परिपाटी, वर्षों से परिपाटी रही है, और विशेष कर बिहार जैसे राज्य में, जब पांच महीना मौनसून का समय है, 30जून के बाद कोई पैसा खर्च नहीं हो सकता है, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, फिर दशहरा, दिवाली, छठ का समय है, यानी जो भी व्यय है, तो वित्तीय वर्ष प्रारभ्भ होता है 01अप्रील से, और जब तक योजनाओं का चयन होता है, प्राक्कलन बनता है तब तक मौनसून प्रारभ्भ हो जाता है, और वास्तविक व्यय होना प्रारभ्भ होता है 30नवम्बर, 01दिसम्बर के बाद से । यह तो बार-बार सरकार इस बात को स्वीकार किया है । हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, कि हम 01दिसम्बर के पहले चाह कर भी व्यय नहीं कर सकते हैं । देश के अन्य राज्यों से भिन्न, बिहार की स्थिति में है, बाढ़ है, वर्षा है, मौनसून है, और अन्तिम चार महीने में भी जो व्यय होता है तो स्वाभाविक है कि अंतिम मार्च महीने में व्यय ज्यादा होता है, लेकिन इसमें लूट का, अगर मानलीजिए कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने 300करोड़ रूपया अंतिम महीने में विथड्रॉ कर लिया, तो क्या वह पैसा लूट लिया जाता है ! वह पैसा बॉंट दिया जाता है ! और, पार्किंग की जहां तक बात आती है, एम0पी0लैड फंड लैप्स नहीं करता है । इसके पहले भी राज्य में विधायक फंड

था, लैप्स नहीं करता है । इस साल नहीं खर्च हुआ, पैसा पड़ा रहता है जिलों के अंदर, अगले साल खर्च होता है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो बी0आर0जी0एफ0 का पैसा है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, अभी 300करोड़ रूपया चार दिन पहले मिला है और अंतिम चार दिन में 500करोड़ रूपया और केन्द्र से मिलने की संभावना है । तो हम क्या करें ! अगर हमको राशि ही मिलती है 20तारीख के बाद, 25तारीख के बाद, और केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा जनवरी में, फरबरी में, मार्च में, अंतिम समय में राज्य को प्राप्त होता है, तो उनका यह निर्देश थोड़े ही है कि आप उस पैसे को 31के पहले खर्च कर दीजिए, उस पैसे को निकाल कर हम जिलों में देते हैं, और आप जो आंकड़ा पढ़ रहे थे, जिसने भी आपको आपूर्त्ति किया, आपके कोई पुराने मित्र रह गए होंगे इस सरकार के अंदर नौकरशाही में, लेकिन वह आंकड़ा सही नहीं है । इस मायने में आप रिवाइज्ड इस्टिमेट का परसेंटेज बता रहे हैं । और हमारा रिवाइज्ड इस्टिमेट 28हजार करोड़ था, और रिवाइज्ड इस्टिमेट का प्रतिशत् आप पढ़ रहे हैं । जो हमारा बजट इस्टिमेट था वह 24हजार करोड़ है जिसको हमने बाद में बढ़ा कर 28हजार करोड़ किया, और हमने यह कहा कि वर्ष के अंत में हम 24हजार करोड़ रूपया व्यय करेंगे और 31तारीख को हमको मालूम होगा कि 24हजार करोड़ में पुनरीक्षित योजना का आकार क्या होगा । चूंकि दो हजार करोड़ हमको झारखंड से मिलना था पेंशन के मद में, हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और संभावना नहीं है अध्यक्ष महोदय कि 31तारीख तक हमको वह दो हजार करोड़ की राशि प्राप्त होगी । तो अगर दो हजार करोड़ हमको नहीं मिलेगा, तो हमारा जो प्लैन का फाइनान्सिंग स्कीम हमने तैयार की है, वह प्रभावित हो जाएगी । केन्द्रीय करों में राज्यों को जो हिस्सा मिलता है, उसका हमने जो आकलन किया, वह आकलन केन्द्र के निर्देश के अनुसार हम आकलन करते हैं, बजट बनाते हैं इसमें कि केन्द्रीय करों में कितना हिस्सा बिहार को मिलेगा, या प्लैनिग कमीशन बताती है आप इतना उसके अंदर प्रावधान कीजिए । और, अभी जब केन्द्रीय बजट 2012-13 का 16मार्च को लोक सभा में पेश हुआ है तब केन्द्रीय बजट में इस बात का उल्लेख है कि राज्यों को 2011-12 में केन्द्रीय करों में कितना मिलेगा । लगभग 870करोड़ रूपया हमको कम मिलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, तो अगर हमको 870रूपया कम मिलेगा, दो हजार करोड़ कम मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो प्लैन का आकर 24हजार करोड़ है, उसमें हमको कटौती करनी पड़ेगी । हम कहां से पैसा लाएंगे ! और जो धन राशि हमको फरबरी में मिली, मार्च में मिली, वह पैसा हमने जिलों को दे दिया, जिलों ने

पंचायतों को दे दिया तो लूट कैसे हो गई ? उस पैसे को कोई लूट कोई कैसे लेगा अध्यक्ष महोदय ? यह बात ठीक है कि वह पैसा मार्च में खर्च नहीं होकर वह पैसा अप्रील में खर्च होगा, मई में खर्च होगा और यही परिपाटी देश के सभी राज्यों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मार्च में खर्च हो जाए । आप कल कहेंगे कि ठीकेदार को पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ ! इसलिए महोदय, जिसको आप पार्किंग कहते हैं, आप उसके लिए जो शब्द प्रयोग करें, लेकिन केन्द्र की सरकार जब मार्च महीने में एक बड़ी धनराशि का हिस्सा राज्य सरकार को देती है, तो स्वाभाविक है कि उस राशि को हम जिलों के अंदर देंगे, जिला प्रंखंड को देगा और राशि खर्च होने में मई, जून, अगस्त भी हो सकता है । इसका मतलब यह लूट कहां है ! और मैं सिद्दिकी साहब को मैंने पिछली बार भी कहा था कि वह दिन बीत गया जब पुलिस को बुलाना पड़ता था सचिवालय के अंदर, और ट्रेजरी के बाहर पुलिस का पहरा रहता था और रात-रात भर चार बजे भोर तक सचिवालय खुला रहता था और भीड़ लगी रहती थी ठीकेदारों और बाकी की, अभी आप जाइये तो छः बजे के बाद सचिवालय बंद मिलेगा । इस राज्य में कोई मार्च के नाम पर लूट करने की हिम्मत नहीं कर सकता है अध्यक्ष महोदय । थपथपी । और अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता, विरोधी दलः हमारा कहना है कि वित्त मंत्री बनने के बाद दाल -चावल का भाव आपको मालुम हो गया । यही जब हमलोग कहते थे कि केन्द्र सरकार हमको चार रोज पहले देती है, पांच रोज पहले देती है , एक महीना पहले देती है, आप क्या बोलते थे नेता विरोधी दल की हैसियत से ! है न याद !

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता,विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था लेकिन यह हालत नहीं थी कि पंद्रह साल शासन किया और योजना आकर डेढ़ हजार करोड़ से चार हजार करोड़ पार नहीं किया अध्यक्ष महोदय । अब बतायें कि 1990 से लेकर 2004-05 तक आपकी सरकार थी । मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा । जब बिहार झारखड एक था तो 12सौ करोड़, 14सौ करोड़, 15सौ करोड़ योजना का आकार था, और आज अगर चार हजार करोड़ से अगर हम चौबिस हजार करोड़ पर पहुंचे हैं और अगले साल अठाइस हजार करोड़ पर पहुंचे हैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि हमलोग अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और अगर यह खर्च नहीं होता तो यह बदलाव दिखाई नहीं पड़ता । अगर यह खर्च नहीं होता तो प्रचंड बहुमत जो जनता ने माननीय मुख्यमंत्री में विश्वास, इस सरकार में प्रकट किया है कि .....क्रमशः.

...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : ...क्रमशः... पूरे दुनिया का रेकर्ड टूट गया कि २४३ में २०६ से ज्यादा विधान सभा में सीट जीतने का काम हमलोगों ने किया । अगर हमलोगों ने काम नहीं किया होता तो केवल हवाबाजी के आधार पर जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जनता इस प्रकार का प्रचंड बहुमत हमलोगों को देने का काम करती । अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने कहा कि हमलोग लगातार खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष के अन्दर जैसा मैंने शुरू में बताया था, माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रत्येक जो माँग है, उसके लिये सदन ने अनुमति प्रदान कर दी है कि शिक्षा विभाग के अन्दर कितना खर्च होगा, ग्रामीण विकास में कितना खर्च होगा और आज यह जो विनियोग विधेयक है, यह राज्य सरकार को एक प्रकार की चाबी उपलब्ध कराती है यानी राज्य की जो समेकित निधि है, उस समेकित निधि से तबतक हम राशि नहीं निकाल सकते हैं, खर्च करने की अनुमति नहीं मिल सकती है जबतक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। अभी तक माननीय सदस्यों ने एक-एक विभाग के बारे में अनुमति दी है कि किस विभाग से कितना पैसा खर्च होगा, इसकी अनुमति आपने दी है लेकिन अब समेकित निधि से जो पैसा निकालना है, उस निकालने की अनुमति इस विनियोग विधेयक के द्वारा सदन से आज सरकार को प्राप्त होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन आज के इस अवसर पर मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो लगातार विकास का प्रयास कर रही है, आज से दो दिन पूर्व दिल्ली के अन्दर, योजना आयोग के अन्दर एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें बिहार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी गये थे, विशेष राज्य के दर्जे पर अपना पक्ष रखने के लिये केन्द्र की सरकार ने, योजना आयोग ने बिहार को आमंत्रित किया था । इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, उसी समय तीन अलग राज्य बने, उत्तराखंड बना, छतीसगढ़ बना और झारखंड बना । एक यू०पी० से, एक मध्य प्रदेश से और एक बिहार से अलग-अलग राज्य बने और जिस समय बिहार पुनर्गठन विधेयक लोक सभा में पेश किया जा रहा था, उस समय अकेला बिहार का पुनर्गठन विधेयक था जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि राज्य अलग होने के बाद योजना आयोग में डिप्टी चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जो इस बात का विचार करेगी कि झारखंड अलग होने के बाद बिहार के विकास की चिन्ता करने के लिये योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा । यह प्रावधान न तो छतीसगढ़ में है, यह प्रावधान उत्तराखंड में नहीं है, केवल बिहार के पुनर्गठन विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया था, मैं उस अंश को पढ़ना चाहूंगा - The Government has set up a unit in Planning Commission under the direct charge of Dy. Chairman, Planning Commission to deal exclusively with the matter relating to the development of rest of Bihar consequent upon formation of Jharkhand. यानी योजना आयोग के अन्तर्गत

प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के सीधे प्रभार में, विशेषकर बिहार के विकास के बारे में विचार करने के लिये झारखंड बनने के बाद जो उत्पन्न परिस्थिति है, उसपर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया जायेगा जो इस बात का विचार करेगी । किसी अन्य स्टेट के पुनर्गठन विधेयक में इसका प्रावधान नहीं है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस समय रेल मंत्री थे और उनके प्रयास से अंतिम समय में यह प्रावधान जोड़ा गया, चूंकि हमको मालूम था कि झारखंड बनने के बाद हमारे अधिकांश संसाधन जब झारखंड में चले जायेंगे तो बाकी बचे बिहार को अगर केन्द्र मदद नहीं करेगा, केन्द्र की सहायता नहीं मिलेगी तबतक बिहार का विकास नहीं हो पायेगा । इसलिये यह प्रावधान किया गया था । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहूंगा, आप सबों को मालूम है, ज्ञात है सदन को कि इस देश में दो तरह के राज्य हैं, एक सामान्य श्रेणी के राज्य और एक है विशेष श्रेणी का राज्य । ११ राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल केटेगरी का दर्जा मिला है, विशेष राज्य का दर्जा मिला है । बाकी सारे राज्य जेनरल केटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के राज्य हैं लेकिन सामान्य श्रेणी के राज्य में, मैंने पिछले भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया था कि यद्यपि बिहार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के साथ सामान्य श्रेणी के राज्यों में शामिल है लेकिन उसमें भी सबसे गरीब राज्यों के अन्दर हम हैं । उस समय में मैंने इस बात का उल्लेख किया था, हम सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, हम स्पेशल केटेगरी में नहीं हैं लेकिन हमारी हालत स्पेशल केटेगरी स्टेट से भी ज्यादा खराब है और प्रगति के सभी मानकों पर विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला है, उनसे भी ज्यादा हम सभी विकास के मानकों पर उनसे पीछे हैं । अब मैं केवल दो-चार आंकड़ा देना चाहता हूं । गरीबी-रेखा से नीचे की बात आती है, अभी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर २००९-१० का आंकड़ा योजना आयोग ने जो प्रचारित किया है, बिहार के अन्दर ५३.५ प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा से नीचे हैं, आधे से ज्यादा लोग और जिनको आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया, उनकी क्या स्थिति है अध्यक्ष महोदय, अरूणाचल प्रदेश में केवल २६ परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, आसाम के अन्दर केवल ३८ परसेंट लोग, हिमाचल में केवल ९.५ प्रतिशत लोग, जम्मू-कश्मीर में केवल ९ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, मणिपुर में ४७ परसेंट लोग, मेघालय में १७ परसेंट लोग, मिजोरम में २१ परसेंट लोग, नागालैंड में २० प्रतिशत, सिक्किम में १३ प्रतिशत, त्रिपुरा में १७ प्रतिशत और उत्तराखंड में १८ प्रतिशत । अध्यक्ष महोदय, कहने को तो हम सामान्य श्रेणी में हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला है, वे हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं, उनके यहाँ तो २० परसेंट से कम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और हमारे यहाँ ५३ प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं । अध्यक्ष महोदय, हम सामान्य श्रेणी के राज्य हैं लेकिन हमारे यहाँ गरीबों की संख्या विशेष श्रेणी के राज्यों से भी कई गुणा ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या है । उसी प्रकार बिजली की अगर हम तुलना करें तो बिहार में में २०१० के आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत ८५ किलोवाट प्रति व्यक्ति है, जबकि हिमाचल प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा जिसको है,

७६५ किलोवाट प्रति व्यक्ति की खपत है हिमाचल में, जम्मू-कश्मीर में ७११ किलोवाट, आसाम के अन्दर १७० किलोवाट और इतना ही नहीं, अगर प्रति व्यक्ति आय से हम तुलना करें तो प्रति व्यक्ति आय आज बिहार की जो २०१०-११ में पर-कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वह राष्ट्रीय औसत की एक-तिहाई है और हिमाचल की तुलना में १/५वें हिस्से पर हम हैं, महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय ६२७२९ रू० है, बिहार का पर-कैपिटा इनकम क्या है - १३६३२ रू०, यानी महाराष्ट्र की तुलना में हम १/५वें हिस्से पर खड़े हैं और देश की औसत की तुलना में हम एक-तिहाई पर हैं । अध्यक्ष महोदय, विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला है, वे तो हमसे एक हजार गुणा बेहतर हैं । उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय ४४ हजार, हमारा है १३ हजार और उनका ४४ हजार, सिक्किम ४७ हजार, हिमाचल ४७ हजार, जिन राज्यों को पिछड़ेपन के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा मिला, वह हमसे कई गुणा ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं और उनको स्पेशल केटेगरी मिलने के कारण यह नहीं है, पहले से वे हमने ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं, फिर भी उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला और आज हम उत्तराखंड के, सिक्किम के, हिमाचल के, नागालैंड छोटा-सा राज्य है, प्रति व्यक्ति आय ४० हजार रूपया, त्रिपुरा ३७ हजार रूपया, मिजोरम ३६ हजार रूपया, मेघालय ३६ हजार रूपया, अरूणाचल ३७ हजार रूपया, मणिपुर २३ हजार रूपया, आसाम २१ हजार रूपया, जम्मू-कश्मीर २७ हजार रूपया और बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है - १३६३२ रूपया ।

अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे लोग दिल्ली में जाकर यह कह रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिये, हम तेजी से विकास कर रहे हैं, हमको और अधिक धन की आवश्यकता है और अगर हम तुलना करते हैं कि देश के जो पिछड़े राज्य हैं, उनकी तुलना में हम काफी पीछे हैं । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, सी०डी० रेशियो के अन्दर आप देखें तो जो उत्तर-पूर्व के राज्य हैं - नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उनका बैंकों में साख जमा अनुपात बिहार की तुलना में बहुत बेहतर है, हम उनसे बहुत पीछे हैं । इसलिये अध्यक्ष महोदय, बार-बार हमारी सरकार कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिये और इतना ही नहीं, अगर आप देखें, किसी भी राज्य के विकास में दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । एक तो योजना का आकार, जो प्लान एलौकेशन है जिसकी अनुमति योजना आयोग देता है और दूसरा है कि उस राज्य में केन्द्र की सरकार कितना निवेश करती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ा जोड़ रहा था, पहली पंचवर्षीय योजना १९५१ में प्रारम्भ हुई है । १९५१ से लेकर ११वीं योजना जो ३१ मार्च को समाप्त होने जा रहा है यह २०११-१२, तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर ११वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल तक बिहार में योजना पर जो खर्च हुआ है, वह १ लाख २१ हजार करोड़ रू० आज तक खर्च हुआ है जिसकी अनुमति योजना आयोग ने दी है । ...क्रमशः...

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : (क्रमशः) जिसकी अनुमति योजना आयोग ने दी और अगर राष्ट्रीय औसत हम देखे अध्यक्ष महोदय कि ५१ में, ५२ में, ६१ में, ७० में, उस समय योजना के आकार का राष्ट्रीय औसत क्या था तो हमारा खर्च होना चाहिए था अध्यक्ष महोदय २ लाख ७८ हजार करोड़ रू० का हमारा योजना आकार आज तक होना चाहिए था और हुआ कितना १ लाख २१ हजार करोड़ और गैप कितना है १ लाख ५७ करोड़ रू०, ५१ से लेकर आज तक राष्ट्रीय औसत से हमारा योजना आकार पीछे है और अगर १ लाख ५७ हजार करोड़ को आज के २०१०-११ के मूल्य पर अगर हम परिवर्तित करे तो ५ लाख ७७ हजार का अन्तर है, गैप है । अगर पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा खर्च राष्ट्रीय औसत के बराबर होता, हमारा खर्च होना चाहिए था ५ लाख ७७ हजार करोड़ और उसकी तुलना में हमारा खर्च हुआ केवल १ लाख २१ हजार करोड़ । अध्यक्ष महोदय, अगर आज बिहार पिछले ५ वर्षों में तेजी से विकास के बाद भी अगर सारे विकास के सभी पैमानों पर नीचे खड़ा है, इसका कारण यह है कि ५१ से लेकर आज तक केन्द्र की सरकार ने बिहार के साथ जो भेद-भाव किया, सौतलेपन का व्यवहार किया और हमारी योजना के आकार का जिस प्रकार से व्यय होना चाहिए था, हमको जो मदद मिलनी चाहिए थी, वह मदद नहीं मिली । उसका परिणाम है कि हम लगातार पिछड़ते चले गये । केन्द्र की सरकार पूँजी का निवेश करती है राज्यों के अन्दर पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग के माध्यम से, बी०आर०जी०एफ० के माध्यम से उसका भी मैं आंकड़ा बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय । २००४-०५ में पूरे देश में भारत की सरकार ने २ लाख ४०हजार करोड़ का निवेश किया राज्यों के अन्दर पूँजी के निर्माण में, इसमें बिहार का हिस्सा कितना है अध्यक्ष महोदय केवल १.३९ यानी २ लाख ४० हजार करोड़ रू० का निवेश हुआ पूरे देश के अन्दर केन्द्र की सरकार के द्वारा और बिहार में हुआ केवल ३३३३ करोड़ जो कुल केन्द्र का निवेश का १.३९ प्रतिशत है और यह प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है अध्यक्ष महोदय । जहां २००४-०५ में केन्द्र ने २ लाख ४० हजार करोड़ का निवेश किया था पूरे देश में, वो २००९-१० में बढ़कर हो गया ६,०१,६१८ करोड़ यानी लगभग दुगुना से ज्यादा लगभग तीन गुना बढ़ गया, २ लाख ४० हजार से बढ़कर ६,०१,६१८ करोड़ का निवेश किया केन्द्र की सरकार ने राज्यों के अन्दर और उसमें बिहार का हिस्सा कितना है अध्यक्ष महोदय केवल ३९०२ करोड़ यानी जहां २००४-०५ में १.३९ प्रतिशत था निवेश केन्द्र का, वह घटकर ०.६५ प्रतिशत पर पहुंच गया । अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं, जो भी सरकारें रही हों इस राज्य के अन्दर ५१ से लेकर आज तक अगर हम राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर रहते, अगर हमारा योजना का आकार और केन्द्र सरकार की पूँजी निवेश होता तो आज जो हमारे राज्य के अन्दर जो स्थिति बनी है अध्यक्ष महोदय कि हम सभी मानकों पर देश के सबसे पिछड़ों राज्यों पर आकर खड़े हो गये हैं तो आज यह स्थिति नहीं बनती । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से मिलने गये थे । उस समय भी उन्होंने इस बात का उल्लेखय किया था कि ....

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसपर हम सब एक हैं । मगर उत्तरांचल को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था, वह कब मिला था और हमको क्यों नहीं मिला ? उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा क्या तत्कालीन एन०डी०ए० हुकुमत ने दिया और उसने बिहार पर विचार नहीं किया, क्या यह सही है ?

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस समय झारखंड अलग हुआ अध्यक्ष महोदय, उस समय नीतीश जी रेल मंत्री थे, केन्द्र में अटल जी की सरकार थी, जिसका मैंने जिक्र किया कि बिहार पुनर्गठन विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया था और इन सब लोगों के प्रयास से बिहार को बी०आर०जी०एफ० के तहत, उस समय राष्ट्रीय सम विकास योजना नाम था अध्यक्ष महोदय, १०वीं एवं ११वीं योजना के अन्तर्गत ९१५६करोड़ का प्रावधान किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें से मिला बिहार को अभी तक केवल ७२९६ करोड़ तो ये बी०आर०जी०एफ० के तहत जिसका पहले राष्ट्रीय सम विकास योजना था जो बाद में बिहार पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान स्टेट कम्पोनेंट में परिवर्तित हो गया, उसमें हमको अभी भी १८६० करोड़ रू० मिलना बाकी है । साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री से इस बात का आग्रह किया है कि हमारे जो स्टेट हाईवे हैं, उसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है, उसके लिए हमको ६४० करोड़ रू० की अतिरिक्त आवश्यकता है । साथ ही साथ गंगा नदी पर रेल सह रोड पुल बन रहा है, उसके पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिए ३९२ करोड़ और इसको एन०एच०-१९ और एन०एच०- ९८ से जोड़ने के लिए ३९२ करोड़ के अतिरिक्त आवश्यकता है, यानी कुल मिलाकर हमको ३१९२ करोड़ रू० की और आवश्यकता है ताकि १०वीं और ११वीं पंचवर्षीय योजना में हमें जो राशि मिलनी थी और जिससे हमारे सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में काफी बड़ा काम हुआ है । इन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से मिलकर इस बात का आग्रह किया है कि हम चाहेंगे कि केन्द्र की सरकार हमारा जो ३१९२ करोड़ रू० जो बाकी है, वह बिहार को मिलना चाहिए ताकि हमारी जो योजनायें अधूरी पड़ी हुई है, हम उन योजनाओं को पूरा कर सके । उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, झारखंड अलग होने के बाद हमारी जो पेंशन की देयता है और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र की सरकार से आग्रह किया है कि ३१.३.२०१० तक ५०३० करोड़ रू० पेंशन के मद में और २८५ करोड़ रू० बौंड के लाईबीलीटीज के मद में झारखंड के पास मेरा बकाया है । यानी दोनों राज्यों का विवाद केन्द्र के गृह मंत्रालय के पास लंबित था, दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद इसका निर्णय जो है, गृह मंत्रालय के पास लंबित है । हमलोगों ने आग्रह किया कि जल्द से जल्द केन्द्र की सरकार अपना निर्णय दे ताकि झारखंड से पेंशन और बौंड की लाईबीलीटीज का जो पैसा है, वह बिहार सरकार को तत्काल मिल सके । साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने यह भी मांग किया है कि जो बी०आर०जी०एफ० के तहत १०वीं और ११वीं योजना में जो पैसा मिल रहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि १२वीं पंचवर्षीय योजना में भी जिस तरह

से हमको १५०० से २००० करोड़ रू० ११ वीं योजना में मिल रहा था प्रारंभ में एक हजार करोड़ और अंतिम वर्ष में २००० करोड़ मिलने की बात हुई थी । १२वीं योजना में भी प्रतिवर्ष बिहार को ४०००करोड़ रू० अतिरिक्त सहायता बी०आर०जी०एफ० स्टेट कम्पोनेंट के मद में मिले यानी अगले ५ साल में २०,०००करोड़ की मदद अगर बिहार को मिलती है तो बिहार अपनी अनेक जो अधूरी योजनायें है, जो योजनायें चल रही है या कुछ नई योजनाओं पर हम काम प्रारंभ कर पायेंगे । इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसका मैंने प्रारंभ में जिक्र किया कि बिहार न तो विशेष राज्य के दर्जे में शामिल है और जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, उसके अन्दर भी बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जो सबसे गरीब राज्यों के पंक्ति में बिहार खड़ा है तो अगर बिहार जैसे १० करोड़ की आबादी के राज्य को देश के बाकी राज्यों के समकक्ष अगर खड़ा करना है तो अगर केन्द्र विशेष मदद नहीं करेगा, विशेष सहायता नहीं देगा, स्पेशल श्रेणी के राज्य में अगर बिहार को शामिल नहीं करेगा तो हमारे सारे प्रयास के बावजूद इस गति से अगर हम विकास करते रहेंगे तो २५ साल में भी हम देश के अन्य राज्यों के समकक्ष नहीं पहुंच पायेंगे । अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी दलों के सदस्यों का यह दायित्व बनता है कि जब राज्य का विकास का मामला है, राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोग केन्द्र की सरकार पर इस बात का दबाव डाले कि हमको १२वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सहायता मिले और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार का लंबित है, वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करता हूँ कि हमारे अधिकारी योजना आयोग में जो ३ दिन पूर्व गये थे और बड़ी मजबूती के साथ उन लोगों ने अपनी बातों को रखा है । मैं उम्मीद करता हूँ कि केन्द्र की सरकार निश्चित रूप से बिहार के तथ्यों एवं तर्कों पर ध्यान देगी और बिहार के अनुकूल निर्णय लेगी ताकि जो हमलोगों का सपना है कि २०१५ तक बिहार विकसित राज्यों के पंक्ति में आकर खड़ा हो सके, उस सपने को हम साकार कर सकें, उस सपने को हम पूरा कर सके । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आग्रह करूँगा कि इस विनियोग विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आजकल एक गीत गाया जा रहा है नेता विपक्ष के द्वारा कि सी०ए०जी० रिपोर्ट, सी०ए०जी० रिपोर्ट, सी०ए०जी० रिपोर्ट, नियम आपका क्या है, विनियोग लेखे, वित्त लेखे अंतिम दिन.......

श्री अब्दुलबारी सिदिकी,नेता विरोधी दल : आप किसकी अनुमति से बोल रहे हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आप बीच में अनुमति लेकर के उठे थे, परम्परा है कि जब तक सरकार क उत्तर होता रहा हो, कम से कम विपक्ष के नेता बीच-बीच में खुद से खड़े नहीं होते लेकिन आपने उस परम्परा को तोड़ा और अपने लिए परम्परा की बात कर रहे हैं ।

.... क्रमशः ....